

प्रेषक,

डॉ० राकेश कुमार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 15/ जनवरी, 2011

विषय:-तहसील नैनीताल/धारी/कोश्या कुटोली/बैतालघाट, जिला नैनीताल में सैनिक विश्राम गृहों की स्थापना हेतु खसरा संख्या-4649, 4972 मध्य 0.080 है०, खसरा संख्या-214 मध्य एक नाली, खसरा संख्या-604 मध्य 0.060 है०, खसरा संख्या-2353 मध्य 0.040 है० एवं खसरा संख्या-488 म० के अधीन 0.040 है० भूमि सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-686/12-ज्येड0ए0सी0/2010, दिनांक-4.10.2010 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, तहसील नैनीताल/धारी/कोश्या कुटोली/बैतालघाट, जिला नैनीताल में सैनिक विश्राम गृहों की स्थापना हेतु ग्राम महारा गांव, तहसील नैनीताल में, खसरा संख्या-4649, 4972 मध्य 0.080 है०, ग्राम च्यूनी, तहसील बैतालघाट में, खसरा संख्या-214 मध्य एक नाली, ग्राम सरनातोप सौकिया पड़ाव, तहसील धारी में खसरा संख्या-604 मध्य 0.060 है०, ग्राम चंभार कोट, पट्टी बेडुली, तहसील कोश्या कुटोली में खसरा संख्या-2353 मध्य 0.040 है० एवं ग्राम छड़ा (गर्म पानी), तहसील कोश्या कुटोली में खसरा संख्या-488 म० के अधीन 0.040 है० भूमि, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को, वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-26/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक-15.02.02 एवं सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गई सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में गैर वानिकी कार्य हेतु, भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० राकेश कुमार)  
सचिव।

पू०प०संख्या-15 /समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय।
- 4- प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(संतोष बडोनी)  
अनुसचिव।